बुधवार, 26 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रविंद्र जडेजा ने पासिंदु को बोल्ड कर उनका पहला टेस्ट शतक बनाने का सपना तोड़ दिया

Page-04

करीना कपूर-पृथ्वीराज की 'दायरा' का नया पोस्टर रिलीज

Page-05

सिंधिया ने लॉन्च किए 'डाक मित्र' और 'डाक सेवा' ऐप

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक देश की पुरानी और सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है, जो अब बदलते समय के साथ तकनीक और नवाचार को अपनाते हुए 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को नए स्वरूप में ढाल रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 'डाक मित्र' और, 'डाक सेवा' ऐप और 14 नवीनीकरण किए गए डाकघरों के शुभारंभ के अवसर पर डाक विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक के लिए केवल कुछ नई पहलों के शुभारंभ का दिन नहीं, बल्कि देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक की विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का अवसर है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय डाक को सरल, तेज, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाना है। उन्होंने कहा, "आज नागरिक की अपेक्षा केवल यह नहीं है कि सरकारी सेवा उपलब्ध हो, वह चाहता है कि सेवा उसके मोबाइल पर उपलब्ध हो, उसकी उंगली के एक स्पर्श पर उपलब्ध हो और वह भी तेज, सरल एवं पारदर्शी तरीके से हो। इस कड़ी में विभाग की पहल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल पुरानी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को नागरिक के इर्द-गिर्द पुनः डिजाइन करना है। 'डाक मित्र' ऐप को डाक सेवकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह डाक, बैंकिंग, बीमा और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को एक ही क्लिक में उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ईरान से कारोबार पर अमेरिका का बड़ा एक्शन

4 भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों की चपेट में

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके राजस्व स्रोतों पर दबाव बढ़ाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों की सूची में चार भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इन कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में भूमिका निभाई थी। कार्रवाई के दायरे में इन कंपनियों से जुड़े कुछ भारतीय नागरिक भी आए हैं।अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, संबंधित कंपनियों पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। यह कार्रवाई अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की ओर से घोषित "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" के एक दिन बाद की गई। इस अभियान का उद्देश्य ईरान के राजस्व स्रोतों पर अंकुश लगाना और उसके साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस का जोखिम बढ़ाना बताया गया है।प्रतिबंधों की सूची में कस्टम्स ब्रोकर पोर्टईज़ पार्टनर्स एलएलपी और उसके पार्टनर इद्रिसमिया अशरफमिया शेख तथा हरीश रामचंद्र रंगी का नाम शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, पोर्टईज़ ने ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के भारत में आयात में सहायता की थी।इसके अलावा सदाशिव ओवरसीज़ लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, सदाशिव ओवरसीज़ ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच ईरान में बने पेट्रोलियम उत्पादों का करीब 69 मिलियन डॉलर का आयात किया। इन लेनदेन में अमेरिका द्वारा पहले से प्रतिबंधित कंपनी बोनजोर कमोडिटी FZE भी शामिल थी।पीपी सॉफ्टटेक पर जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 25 मिलियन डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप है। कंपनी के निदेशक प्रशांत गर्ग को भी प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है।वहीं, प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच करीब 25 मिलियन डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, इस कारोबार में भी बोनजोर कमोडिटी FZE से जुड़े लेनदेन शामिल थे। अमेरिकी बयान के अनुसार, इद्रिसमिया अशरफमिया शेख, हरीश रामचंद्र रंगी और प्रशांत गर्ग भारतीय नागरिक हैं। ताजा प्रतिबंधों से भारत और ईरान के बीच ऊर्जा कारोबार पर अमेरिकी दबाव का नया आयाम सामने आया है। अब भारतीय कंपनियों के लिए ईरान के साथ कारोबार करते समय अमेरिकी प्रतिबंधों और सेकेंडरी सैंक्शंस के जोखिम को ध्यान में रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

दिल्ली में BJP के अंदर से उठे सवाल! विजय गोयल ने MCD अफसरों पर साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े बुनियादी काम कराने के लिए भी अधिकारियों के पीछे भागना पड़ रहा है। गोयल ने कहा कि जब सांसद, विधायक और पार्षद अधिकारियों से काम कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा?गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि यह विडंबना है कि MCD और सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सांसद, विधायक और पार्षद गलियों और सड़कों के चक्कर काटकर उनसे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं से कूड़ा उठवा दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया गया हो, जबकि सवाल यह होना चाहिए कि अधिकारियों की मौजूदगी में वहां कूड़ा जमा ही क्यों हुआ। उन्होंने नालियों, खड़ंजों, सड़कों, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी मुद्दा उठाया। गोयल के मुताबिक, इन समस्याओं को लेकर चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकारियों से बार-बार आग्रह करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में समय पर काम नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में आम नागरिकों की सुनवाई आखिर कौन करेगा।

गोवा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान

सरकार बनी तो 5 दिन में E20 पेट्रोल पर लगेगी रोक

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद गोवा में AAP की सरकार बनती है, तो सरकार बनने के पांच दिनों के भीतर राज्य में E20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।गोवा के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने E20 टाउन हॉल कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "अगर 10 मार्च 2027 के बाद गोवा में हमारी सरकार बनती है, तो पांच दिन के अंदर E20 पेट्रोल बंद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।" उनके इस बयान के बाद गोवा में E20 पेट्रोल का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव का प्रमुख राजनीतिक विषय बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में AAP के दो विधायक हैं।इससे पहले सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 फ्यूल नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इथेनॉल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर गन्ने का इस्तेमाल किए जाने से चीनी की कीमतों पर असर पड़ा है और आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ वाहन मालिकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी और E20 के तकनीकी तथा आर्थिक प्रभावों पर चर्चा के लिए टाउन हॉल बैठक आयोजित करेगी। उन्होंने दावा किया कि कई वाहन निर्माता कंपनियों ने भी E20 ईंधन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) का हवाला देते हुए कहा कि संगठन ने E20 के वाहनों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग की थी। केजरीवाल का आरोप है कि बाद में इस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।AAP प्रमुख ने यह भी कहा कि ब्राजील जैसे देश को E20 ईंधन अपनाने में कई दशक लगे, जबकि भारत में इसे बहुत कम समय में लागू किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि E20 पूरी तरह वैज्ञानिक और सुरक्षित नीति है, तो इसके खिलाफ उठने वाली तकनीकी और उपभोक्ता संबंधी चिंताओं को गंभीरता से क्यों नहीं सुना जा रहा।

मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख

महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने को लेकर विवाद लगातार जारी है। मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के खिलाफ ऑटो रिक्शा और कैब चालकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में अधिवक्ता विवेक शुक्ला के माध्यम से एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12 अगस्त 2026 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य किया गया है। मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका के मामले को तत्काल निर्देशों के लिए बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) रविंद्र घुगे की पीठ के समक्ष मेंशन किया जाएगा। हालांकि, एसीजे रवींद्र घुगे, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की गई है, ने हाल ही में कहा था कि पीठ कोई नया मामला नहीं सुनेगी। याचिकाकर्ताओं में मोहम्मद कासिम अहमद समेत चार ऐप आधारित कैब चालक शामिल हैं। उनका कहना है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही, यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के भी खिलाफ है, क्योंकि इस कानून में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भाषा की अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है।

बांके बिहारी मंदिर के दान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

दान की एक-एक पाई मंदिर के खजाने में जमा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम को लेकर बड़ा निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मंदिर को दान में मिलने वाली पूरी राशि, चाहे वह दानपात्र के जरिए प्राप्त हो या ऑनलाइन माध्यम से, सीधे मंदिर के खजाने में जमा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि सेवायत या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दान की रकम के संग्रह या जमा करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने मंदिर की प्रबंधन समिति को दान की रकम के प्रबंधन के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया, ताकि वित्तीय अनियमितताओं की किसी भी संभावना को रोका जा सके।सुनवाई के दौरान वकील एनके गोस्वामी ने मंदिर के फंड में कथित वित्तीय गड़बड़ी और करोड़ों रुपये के गबन के आरोप लगाए। इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। पीठ ने कहा कि दान की रकम को लेकर किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए और मंदिर में आने वाला प्रत्येक पैसा निर्धारित व्यवस्था के तहत मंदिर के खजाने में ही जमा होना चाहिए।अदालत ने यह भी साफ किया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की निगरानी और उसके प्रबंधन के लिए पारदर्शी प्रणाली बेहद जरूरी है। इसका उद्देश्य दान की रकम के इस्तेमाल और संग्रह की पूरी प्रक्रिया को जवाबदेह बनाना है।

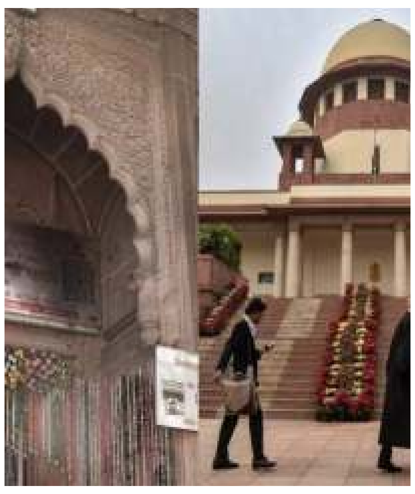

हिन्दी जगत महामंच

tv भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1

प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़

ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2-3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

✆ 8601780000

H-1B वीजा पर ट्रंप का बड़ा झटका!

ज्यादा फीस के प्रस्ताव से भारतीय छात्रों-प्रोफेशनल्स की बढ़ी चिंता

ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा की फीस 1,03,265 डॉलर करने के प्रस्ताव ने भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ा दी है।अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों और विदेशी कर्मचारियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा।नई फीस से भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में नौकरी और करियर की राह और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव ने अमेरिका में नौकरी और करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने H-1B वीजा आवेदन के लिए 103,265 डॉलर की फीस लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे अमेरिका में मौजूद विभिन्न देशों के छात्रों और वहां काम कर रहे विदेशी प्रोफेशनल्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है। यह नई फीस सिर्फ विदेश से आवेदन करने वालों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि ज्यादातर नए H-1B वीजा आवेदकों पर लागू हो सकती है।अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस प्रस्ताव को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया है। अगर इसे अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो यह फीस स्थायी रूप से लागू हो सकती है। ट्रंप प्रशासन इसे साल के अंत तक अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का यह प्रस्ताव पहले की एक लाख डॉलर H-1B वीज़ा फीस प्रस्ताव के ठीक बाद आया है। इस प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में घोषित किया था और बाद में इस साल जून में एक अमेरिकी अदालत ने इसे रोक दिया था। अब इस रोक की मियाद 21 सितंबर को खत्म होने वाली है। ट्रंप प्रशासन ने नई फीस को सही ठहराया है। DHS का कहना है कि नई फीस अमेरिका की कानूनी आव्रजन व्यवस्था के प्रशासनिक खर्चों की भरपाई के लिए लगाया जाना जरूरी है।DHS ने साफ किया कि नई फीस सिर्फ कैप-सब्जेक्ट H-1 B वीज़ा एप्लीकेशन पर लागू होगी। अभी, अमेरिका एक फाइनेंशियल ईयर में दिए जाने वाले H-1B वीज़ा की संख्या को 65,000 तक सीमित करता है, और एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स को 20,000 और वीज़ा दिए जाते हैं। कैप-एग्जेम्प्ट H-1 B वीज़ा एप्लीकेशन (जिनका इस्तेमाल आमतौर पर नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन और यूनिवर्सिटी करते हैं) को यह एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। ड्राफ़्ट नोटिस में लिखा है, "DHS का मानना है कि कैप-सब्जेक्ट H-1B पिटीशनर एक्स्ट्रा 103,265 डॉलर फीस देने को तैयार हैं और वहन कर सकते हैं। H-1B कैप-सब्जेक्ट पिटीशन में इस प्रस्तावित फीस को जोड़ने का मकसद फ़ेडरल सरकार को कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को चलाने के कुछ खर्चों की भरपाई के लिए रेवेन्यू का एक खास सोर्स देना है, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट और एजेंसियों द्वारा किए गए कुछ खर्च भी शामिल हैं।"विभाग के अनुमान के मुताबिक, करीब 85,000 वीजा याचिकाओं से सरकार को लगभग 8.8 अरब डॉलर का राजस्व मिल सकता है। इस राशि का इस्तेमाल DHS के साथ-साथ श्रम विभाग, विदेश विभाग और न्याय विभाग सहित अन्य सरकारी एजेंसियों की कानूनी आव्रजन व्यवस्था से जुड़े खर्चों की भरपाई में किया जा सकता है। DHS ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पहले वाली 100,000 डॉलर की फीस से जुड़ी राष्ट्रपति घोषणा कानूनी चुनौतियों में बच जाती है और उसे आगे बढ़ाया या नवीनीकृत किया जाता है, तो दोनों शुल्क एक साथ लागू हो सकते हैं। ऐसे में H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले नियोक्ताओं और विदेशी पेशेवरों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।H-1B वीजा के जरिए ही अमेरिका की कंपनियां खास तकनीकी दक्षता वाले विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं। बिना H-1B वीजा के विदेशी लोगों को अमेरिका मं नौकरी नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्त जैसे सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस वीजा का इस्तेमाल होता है। हर साल 65 हजार सामान्य H-1B वीजा जारी किए जाते हैं। वहीं एडवांस डिग्री वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए 20 हजार अतिरिक्त वीजा का प्रावधान है। H-1B वीजा तीन से 6 साल के लिए मंजूर किए जाते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पहले H-1B वीजा की फीस आम तौर पर 2 से 5 हजार डॉलर के बीच होती थी। वहीं अब इसे 103,265 डॉलर करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बुर्का, नकाब, हिजाब सब पर लगा बैन, किस देश में आ गया नया आदेश!

फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली जैसे देशों के बाद अब एक बड़ा फैसला एक और देश ने लिया है जिसका सीधा सरोकार मुस्लिम महिलाओं से है। फैसला यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर यह महिलाएं निकलती हैं तो यह बुर्का नहीं पहन पाएंगी। नकाब से अपना चेहरा नहीं ढक पाएंगी। पुर्तगाल ने फैसला लिया है। खबर यह मिल रही है कि यह वो देश है जिसकी आबादी है 1 करोड़। यहां पर मुसलमान है 0.4 टू 0.6% यानी कि 400 से 60 हजार की आबादी है मुसलमानों की पुर्तगाल में। यह यूरोप के सबसे पश्चिमी इलाके में पड़ने वाला एक ऐसा देश है जिसकी जो थल सीमा है वो सिर्फ स्पेन से लगती है और यहां पर यह फैसला लिया गया है कि अगर महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर जाना है पब्लिक प्लेस में जाना है तो वह अपना चेहरा नकाब से नहीं ढक सकती हैं। सिक्योरिटी रीज़ंस के साथ-साथ महिलाओं को आजादी देने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। पुर्तगाल में यह फैसला लिया गया है और किसी ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि इस फैसले को वहां की महिलाओं ने हाथों-हाथ लिया है। यानी जो पुर्तगाल में रहने वाली महिलाएं हैं खासकर मुस्लिम महिलाएं वो अब ना तो बुर्का पहन पाएंगी ना नकाब लगा पाएंगी और यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वो भी आजादी से जी सके और सिक्योरिटी रीज़ंस की वजह से भी यह बड़ा डिसीजन पुर्तगाल की सरकार ने लिया है। अब दुनिया भर के कई देशों में यूं तो बुर्का बैन है। हिजाब बैन है, नकाब बैन है। लेकिन फिर भी भारत में जब आप आएंगे तो इस पर एक नई बहस छिड़ जाती है। यहां तक कि स्कूलों में भी अगर कोई टीचर हिजाब पर टोक दे या कह दे कि आपको प्रॉपर यूनिफार्म में आना है। आपको अपने रिलीजियस चीजों को स्कूल में जहां पर यूनिफॉर्मिटी को बढ़ावा दिया जाता है। सब समान है। इसीलिए वहां पर यूनिफार्म होती है। वहां पर भी अगर आप कोई हिजाब पहन कर जा रहा है तो उस पर भी अगर रोक लगा दी जाए तो बवाल हो जाता है। कर्नाटक का पूरा मामला हम सबके सामने है।

मंदिर में दर्शन को लेकर हुई बहस के बाद ये घटना हुई।
थप्पड़ लगने के बाद सब इंस्पेक्टर ने भी जवाबी थप्पड़ विधायक की बेटी को रसीद दिया।

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गुजरात के स्कूलों की तुलना करने की सीधी चुनौती दी

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी को चुनौती दी कि वे पंजाब और गुजरात के 1,000 सरकारी स्कूलों की तुलना करें। साथ ही, उन्होंने बीजेपी पर पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने के लिए "छेड़छाड़ किए गए AI वीडियो" का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। एक वीडियो मैसेज में केजरीवाल ने कहा कि वह पंजाब के 1,000 स्कूलों की लिस्ट देंगे और बीजेपी से कहा कि वे गुजरात के 1,000 स्कूलों के नाम बताएं ताकि मीडिया की मौजूदगी में दोनों जगहों के स्कूलों का संयुक्त निरीक्षण किया जा सके।केजरीवाल ने वीडियो मैसेज में कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं: आप गुजरात में 30 साल से सत्ता में हैं और हम पंजाब में साढ़े चार साल से सत्ता में हैं। मैं आपको पंजाब के 1,000 स्कूलों की लिस्ट दूंगा और आप हमें गुजरात के 1,000 स्कूलों की लिस्ट दें। आइए, हम मिलकर इन स्कूलों का निरीक्षण करें और देखें कि कौन से स्कूल बेहतर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP शासित राज्य अपने खुद के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बजाय पंजाब के स्कूलों की आलोचना करने पर ध्यान दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ़ साढ़े चार साल में हमने पंजाब के स्कूलों को बहुत बेहतर बना दिया है। पंजाब में लगभग 19,700 स्कूल हैं, जिनमें से सिर्फ़ 500 स्कूल ही बाकी रह गए हैं। हमने बाकी 19,200 स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया है। उन 500 स्कूलों में भी काम चल रहा है और अगले डेढ़ से दो साल में उन्हें भी ठीक कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि 2022 में AAP के सत्ता में आने के बाद से पंजाब के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है; उस समय राज्य 28वें स्थान पर था। केजरीवाल ने कहा कि हमने अकेले स्कूलों को बेहतर नहीं बनाया; पंजाब के लोगों ने पंजाब के स्कूलों को बेहतर बनाया। पंजाब के टीचरों ने उन्हें बेहतर बनाया, पंजाब के प्रिंसिपलों ने उन्हें बेहतर बनाया, माता-पिता और बच्चों - सभी ने मिलकर उन्हें बेहतर बनाया।

ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक नया वीडियो जारी

ईरान ने पहली बार अपने सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई का एक धार्मिक एकेडमिक स्टडी सेशन की अध्यक्षता करते हुए दुर्लभ फुटेज जारी किया है। वीडियो में, 56 वर्षीय नेता एक छात्र को थीसिस पेश करते हुए सुन रहे हैं और उस काम पर अपनी राय दे रहे हैं। यह घटनाक्रम मोजतबा की सेहत को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच सामने आया है। खबरों के अनुसार, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के मिले-जुले हमलों में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे; इन हमलों में उनके पिता और उनसे पहले इस पद पर रहे अली खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान की फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा शेयर किए गए इस पहले कभी न देखे गए वीडियो में मुज्तबा की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसमें वह छात्रों को ईरानी सरकार के "इस्लामिक सुरक्षा मॉडल" के बारे में समझा रहे हैं। वीडियो में, मोजतबा अपने छात्र की थीसिस को 20 में से 19.5 नंबर देते हैं और उसे "बेदाग" बताते हैं। बिना तारीख वाले इस वीडियो में ईरानी नेता की एक दुर्लभ झलक मिलती है, जबकि दुनिया भर में ईरान के राजनीतिक और सैन्य ढांचे में उनकी पर्दे के पीछे की भूमिका और नेतृत्व पर चर्चा हो रही है। हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था। अपने पिता अली खामेनेई की हत्या के बाद, 56 साल के मोजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से मोजतबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। कई अमेरिकी अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि 28 फरवरी के हमलों में उनके "चेहरे और पैर" पर गंभीर चोटें आई थीं और वे अभी भी उनसे उबर रहे हैं।

बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट फिर छा गया, फंडिंग कम हो रही

बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट एक बार फिर गंभीर हालात पर पहुंच गया है। करीब दस लाख रोहिंग्या अब भी बांग्लादेश के कैंपों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन मदद का पैसा लगातार कम हो रहा है। इसका सीधा असर कैंपों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अगर जल्द मदद नहीं मिली, तो यह संकट और बड़ा हो सकता है। 25 अगस्त 2017 को म्यांमार के रखाइन राज्य से बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे थे। अब इस संकट को करीब नौ साल पूरे हो चुके हैं और दसवां साल शुरू हो गया है। इतने लंबे समय के बाद भी उनकी म्यांमार वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने कहा कि रोहिंग्या संकट के लिए मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय फंडिंग कम हो रही है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ज्यादा मदद जुटाने की कोशिश कर रहा है। सियाम के मुताबिक, बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर उठाता रहेगा। उनका कहना है कि म्यांमार पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाए रखना जरूरी है। ताकि भविष्य में रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी का रास्ता खुल सके। कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंप लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं। ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल भी यहां लंबे समय से काम कर रहा है। संगठन की सीईओ महमूदा खान के मुताबिक, पिछले एक साल में रोहिंग्या संकट को लेकर दुनिया का ध्यान कम हुआ है। कई दूसरे अंतरराष्ट्रीय संकट सामने आने के कारण रोहिंग्या मुद्दा पीछे छूट गया है। इसका असर फंडिंग पर भी पड़ा है। सरकारों और डोनर्स से पहले की तुलना में कम पैसा मिल रहा है। नतीजा यह है कि कैंपों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। कैंपों में रहने वाले रोहिंग्याओं के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है। राशन पर्याप्त नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित हैं। 30 साल के रोहिंग्या हुसैन जोहर 2017 में कुटुपालोंग कैंप पहुंचे थे। उनका कहना है कि राशन बढ़ाने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक्सपर्ट को डर है कि अगर इन जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, तो इसका असर सिर्फ कैंपों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे इलाके में अस्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। महमूदा खान का कहना है कि इस संकट को खत्म करने का एक रास्ता लगातार जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया को रोहिंग्याओं की स्थिति के बारे में बताते रहना होगा। ताकि यह संकट भुलाया न जाए और जरूरी मदद फिर से जुटाई जा सके।

संपादक की कलम से

महाराष्ट्र भाजपा में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्ति को केवल संगठनात्मक फेरबदल के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनावी तैयारी कभी खत्म नहीं होती। भाजपा की नई नियुक्तियां इस बात का संकेत हैं कि पार्टी अभी से समाज के अलग-अलग वर्गों और पेशागत समूहों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।कानून, उद्योग, चिकित्सा, सहकारिता, व्यापार, शिक्षा, युवा, कामगार, सोशल मीडिया और मीडिया जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय करना बताता है कि आधुनिक राजनीति में संगठन की भूमिका कितनी व्यापक हो चुकी है। अब चुनाव केवल रैलियों और भाषणों के सहारे नहीं जीते जाते। मतदाता तक लगातार संवाद, स्थानीय मुद्दों की समझ और डिजिटल माध्यमों पर मजबूत उपस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है।महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से विविध राज्य में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, बंगाली, जैन, मछुआरा, बुनकर और घुमंतु समाज जैसे अलग-अलग समूहों के लिए प्रकोष्ठ बनाना भाजपा की सामाजिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। यह रणनीति तभी सफल होगी जब इन प्रकोष्ठों को केवल चुनावी समय की गतिविधियों तक सीमित न रखकर पूरे पांच वर्ष सक्रिय रखा जाए।सोशल मीडिया और आईटी प्रकोष्ठों को दी गई जिम्मेदारियां भी बदलती राजनीतिक संस्कृति की ओर संकेत करती हैं। आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तय होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए तथ्यात्मक और जिम्मेदार संवाद स्थापित करना जरूरी है। केवल प्रचार और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से संगठन मजबूत नहीं होता; जनता के सवालों का जवाब देना भी उतना ही आवश्यक है।भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती नियुक्तियां करने के बाद इन पदाधिकारियों को प्रभावी ढंग से काम करने की स्वतंत्रता और संसाधन उपलब्ध कराने की होगी। संगठन का विस्तार तभी सार्थक है, जब उसका लाभ आम कार्यकर्ता और आम नागरिक दोनों को दिखाई दे।2029 की राह लंबी है। महाराष्ट्र भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारी का संकेत दे दिया है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि ये नई जिम्मेदारियां कागज से निकलकर जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। लोकतंत्र में मजबूत संगठन जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है जनता के प्रति जवाबदेही। अंततः चुनावी सफलता का फैसला पदाधिकारियों की संख्या नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से होगा।

2029 की तैयारी में BJP का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल

महाराष्ट्र में मंत्रियों-विधायकों को मिली अहम जिम्मेदारी

महाराष्ट्र भाजपा की इस नई सूची में मंत्रियों, विधायकों, पूर्व सांसदों और प्रमुख सामाजिक चेहरों को शामिल किया गया है। नई जिम्मेदारियों के जरिए पार्टी ने कानून, उद्योग, चिकित्सा, सहकारिता, व्यापार, सोशल मीडिया, मीडिया, उत्तर भारतीय समाज, कामगार, शिक्षक, युवा और विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़े प्रकोष्ठों को सक्रिय करने पर जोर दिया है।

भाजपा (BJP) ने 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब महाराष्ट्र भाजपा ने भी विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्तियां घोषित कीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने सोमवार को इन नियुक्तियों का ऐलान किया। महाराष्ट्र भाजपा की इस नई सूची में मंत्रियों, विधायकों, पूर्व सांसदों और प्रमुख सामाजिक चेहरों को शामिल किया गया है। नई जिम्मेदारियों के जरिए पार्टी ने कानून, उद्योग, चिकित्सा, सहकारिता, व्यापार, सोशल मीडिया, मीडिया, उत्तर भारतीय समाज, कामगार, शिक्षक, युवा और विभिन्न सामाजिक समूहों से जुड़े प्रकोष्ठों को सक्रिय करने पर जोर दिया है। भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी भूषण महाडिक बनाए गए हैं। वहीं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी विश्वास पाठक को दी गई है। उद्योग प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष अरुण लखानी होंगे, जबकि चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभार भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भारती पवार को सौंपा गया है। बता दें कि अरुण लखानी महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं और विधान परिषद के सदस्य (MLC) हैं। भाजपा ने उन्हें चंद्रपुर-वर्धा-गढ़चिरौली विधान परिषद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। लखानी के बेटे सारंग का विवाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से हुआ है। रेवती एनसीपी संस्थापक शरद पवार की पोती हैं। भाजपा ने सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रभारी विधायक प्रवीण दरेकर को बनाया है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार को दी गई है। शिक्षक और स्नातक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सुनील लोंढा को मिली है।व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी मुंबई के कोषाध्यक्ष किरीट भंसाली होंगे, जबकि आर्थिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलिंद कानडे को दी गई है। भाजपा ने महाराष्ट्र में अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों तक संगठन की पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रकोष्ठों में नियुक्तियां की हैं। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का प्रभारी आर. डी. यादव को बनाया गया है। वहीं दक्षिण भारतीय प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राजेश पिल्ले और बंगाली प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी शुभानत दास को दी गई है। घुमंतु प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीचंद पडलकर होंगे। जैन समाज प्रकोष्ठ का प्रभार महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा को सौंपा गया है। जबकि मछुआरा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी चेतन पाटील, बुनकर प्रकोष्ठ की मनोज द्विवटे और कामगार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलिंद तुलसकर को दी गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ने डिजिटल संगठन को भी महत्व दिया है। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की प्रभारी श्वेता शालिनी बनाई गई हैं, जबकि आईटी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी तेजस मालवीया को दी गई है। मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये को सौंपा गया है। वहीं सुशासन प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी प्रदीप पेशकार को दी गई है। विदेश संबंध विभाग के प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भाजपा के प्रदेश महासचिव सुनील राणे को मिली है। दिव्यांग प्रकोष्ठ में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड को प्रभारी बनाया गया है, जबकि जयसिंग कुणावर चव्हान को सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी तुषार भोसले, ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ के अनूप मोरे, परिवहन से जुड़े रेल यात्री प्रकोष्ठ के कैलास वर्मा और इंजीनियर प्रकोष्ठ के प्रशांत ठाकुर बनाए गए हैं।

मंत्री जोगी रमेश ने अपने परिवार के विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाया

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री जोगी रमेश ने अपने परिवार के विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे राजीव और बहू मेघना के वैवाहिक विवाद को लेकर अपने परिवार का बचाव किया है। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को लेकर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। जोगी रमेश ने कहा कि शादी के बाद राजीव और मेघना के बीच मतभेद सामने आने पर परिवार ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि, बाद में राजीव ने तलाक के लिए आवेदन किया। रमेश ने कहा कि इसके बावजूद वह मेघना को अपनी बेटी की तरह ही मानते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण से जुड़े आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया- अगर मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती हैं या ईसा मसीह की शिक्षाएं सुनती हैं तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि उनका परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है और मंदिरों में जाकर पूजा-पाठ व हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेता है। पूर्व मंत्री रमेश ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो, ऑडियो क्लिप और AI से तैयार की गई सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ये सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और समर्थकों से जुड़े प्लेटफॉर्मों पर भी ऐसी चीजें शेयर की जा रही है। बता दें कि मेघना ने थाने में जोगी रमेश के परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जोगी रमेश समेत परिवार के 11 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में धार्मिक धर्मांतरण को लेकर भी आरोप सामने आए हैं। इसके बाद परिवार ने कानूनी राहत के लिए अदालत का रुख किया है। जोगी रमेश ने आरोप लगाया कि मायलावरम से TDP विधायक वसंता कृष्ण प्रसाद ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि हर परिवार में निजी विवाद हो सकते हैं, तो उनके परिवार के मामले को ही बार-बार राजनीतिक और मीडिया मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। रमेश ने उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या NTR, ANR या चिरंजीवी के परिवारों में कभी निजी विवाद नहीं हुए? रमेश ने आरोप लगाया कि TDP के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में लौटने के बाद से ही उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जोगी रमेश कभी गलत काम नहीं करेगा। मैं राजनीतिक रूप से किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हूं।

आठवले ने विरोधियों पर राजद्रोह की कार्रवाई की मांग

चिराग बोले- आरक्षण खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार

केंद्रीय मंत्री एवं 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)' के प्रमुख रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों या इसे खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की रविवार को मांग की। उन्होंने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। आठवले ने एक बयान में कहा कि आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन (जिनमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर घोषित प्रदर्शन भी शामिल हैं) ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने या उसमें बदलाव की मांग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। आठवले ने कहा, 'आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है। जो लोग आरक्षण-विरोधी रुख अपनाते हैं, वे संविधान-विरोधी हैं और उनके खिलाफ राजद्रोह के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। जातिगत आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने 10 फरवरी 2020 को देश की संसद में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। चिराग पासवान ने कहा, 'मेरी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं है।' दिल्ली के जंतर-मंतर पर यूजीसी रिफॉर्म में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नए यूजीसी रिफॉर्म का विरोध करते हुए आरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति जताई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी रिफॉर्म में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार और यूजीसी से इस मामले में हस्तक्षेप कर अपनी मांगों पर विचार करने की अपील की। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनकी मांगों को जल्द सुना जाना चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। (भाषा के इनपुट के साथ)

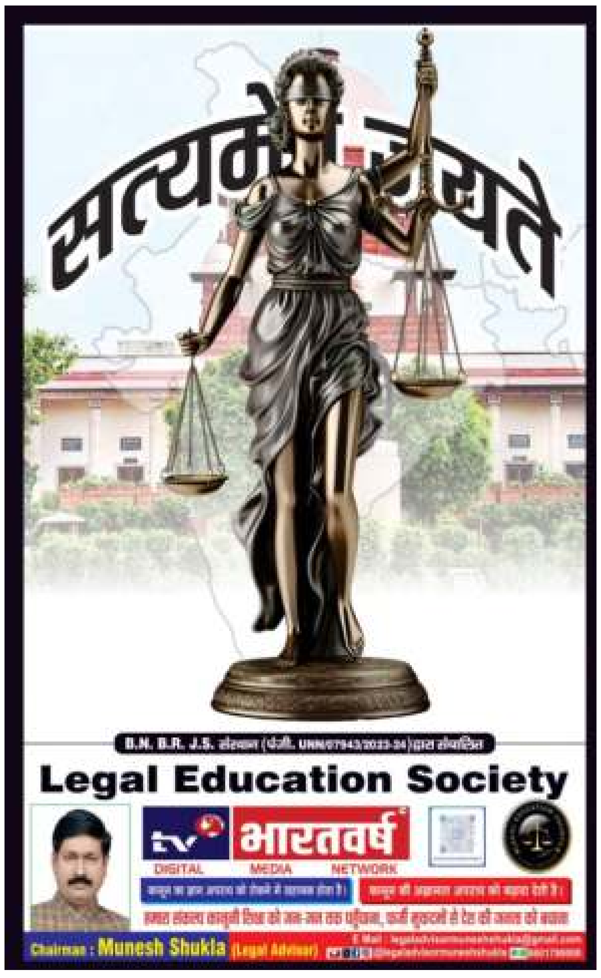
B.N. B.R. J.S. संस्थान (पंजी. UNN07943/2023-24) द्वारा संचालित
Legal Education Society
tv भारतवर्ष DIGITAL MEDIA NETWORK
Chairman : Munesh Shukla (Legal Advisor)

डिग्री-डिप्लोमा के बाद भी नौकरी नहीं! भारत में 4.34 करोड़ छात्र सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को नौकरी

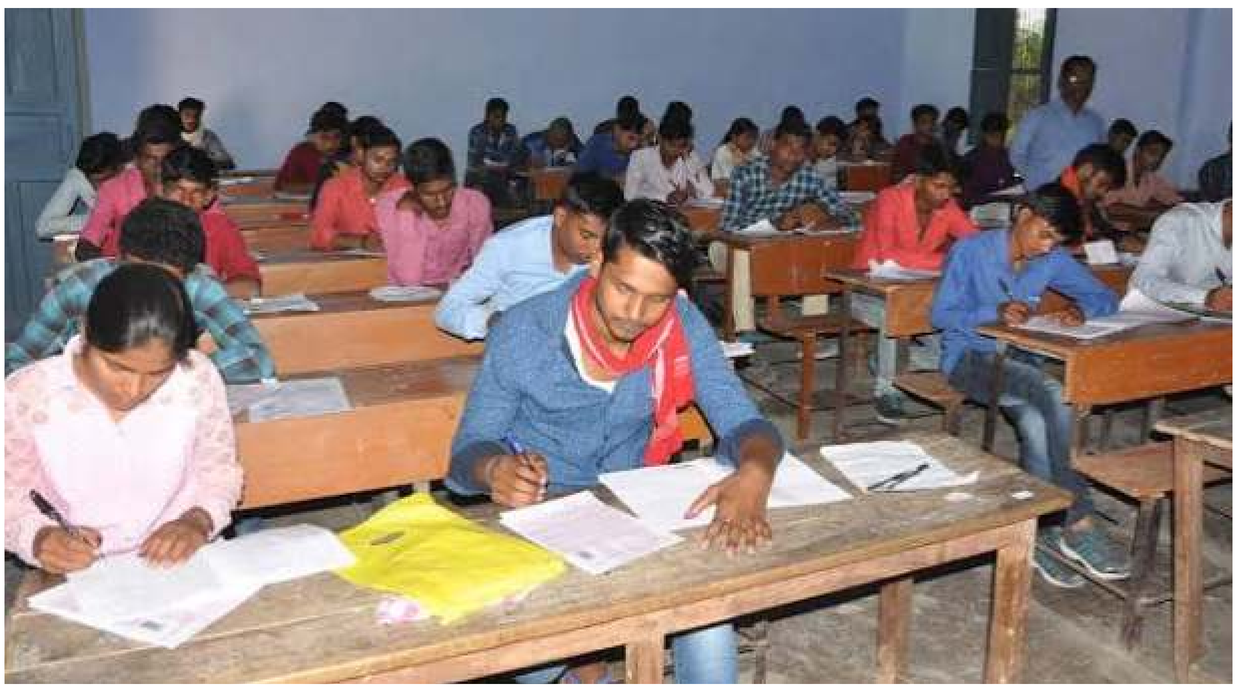

India's Youth Unemployment Crisis: भारत में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वाले युवाओं की कमी नहीं है। वर्तमान में 4.34 करोड़ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज (ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट डिग्री) ले रहे हैं, जबकि डिप्लोमा या ITI स्टूडेंट्स की संख्या 44 लाख के पार है। फिर भी पिछले साल सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स उम्मीदवारों को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ नीति आयोग की नई रिपोर्ट यह भी बताती है कि डिग्री-डिप्लोमा करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। दरअसल नीति आयोग ने हाल ही में 'Reimgining Skilling for Viksit Bharat @2047' रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 'विकसित भारत 2047' के लिए स्किलिंग, रोजगार और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल के रोडमैप पर आधारित है। इससे पता चलता है कि देश में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के बावजूद युवाओं की बड़ी संख्या नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन डिग्री-डिप्लोमा के बाद भी नौकरी की गांरटी क्यों नहीं है? नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के आंकड़ों के साथ इसके पीछे की वजह भी बताई गई है।दरअसल नीति आयोग ने हाल ही में 'Reimgining Skilling for Viksit Bharat @2047' रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 'विकसित भारत 2047' के लिए स्किलिंग, रोजगार और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल के रोडमैप पर आधारित है। इससे पता चलता है कि देश में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के बावजूद युवाओं की बड़ी संख्या नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन डिग्री-डिप्लोमा के बाद भी नौकरी की गांरटी क्यों नहीं है? नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के आंकड़ों के साथ इसके पीछे की वजह भी बताई गई है।नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 बताते हैं कि देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिली है, लेकिन पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जिन उम्मीदवारों के पास बैचलर डिग्री है, उनमें से 13% बेरोजगार हैं, जबकि महिला ग्रेजुएट्स के मामले में यह प्रतिशत 20.4% है, जो 3.2 की राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर से अधिक है। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बाद भीयुवाओं को नौकरी नहीं मिलती। इसके पीछे एजुकेशन-टेक्निकल नॉलेज और जॉब मार्केट की डिमांड में बड़ा फर्क है। रिपोर्ट बताती है कि एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए भी स्किल्स की जरूरत है। लेकिन 34% स्टूडेंट्स स्किल्स की कमी झेल रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। डिग्री कॉलेजों, ITI और पॉलिटेक्निक के बीच यह संतुलन बताता है कि इंडस्ट्री की मजबूत भागीदारी और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए उच्च शिक्षा को नए सिरे से सोचने की कितनी जरूरत है। ये पार्टनरशिप सिलेबस को नए जमाने के हिसाब से बनाने, नौकरी से जुड़ी शिक्षा को शामिल करने और यह पक्का करने के लिए बहुत जरूरी हैं कि स्किलिंग आधुनिक, काम की और असल रोजगार के नतीजों से जुड़ी हो। सबसे पहले, सामान्य डिग्री वाले रास्तों से आगे बढ़कर खास, नौकरी से जुड़े प्रोग्राम की ओर बढ़ने की जरूरत है, खासकर PPP के इस बड़े दायरे में, स्किलिंग हब एक अहम डिलीवरी मैकेनिज्म के तौर पर काम कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री की भागीदारी को सीधे कैंपस तक लाते हैं। ये हब इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बड़े पैमाने पर एंकर लैब, प्रैक्टिशनर-आधारित फैकल्टी मॉडल, क्रेडिट वाली इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, और लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को चलाने में मदद करेंगे।

सीधे नौकरी करने फ्रांस जा सकते हैं भारतीय वर्कर्स, मिल रहा ये खास वीजा

भारतीय प्रोफेशनल्स बिना किसी फ्रेंच जॉब ऑफर या कंपनी स्पॉन्सरशिप के भी फ्रांस जा सकते हैं। फ्रांसीसी सरकार भारतीय प्रोफेशनल्स को 'प्रोफेशन लिबेरेल वीजा' देती है। ये एक तरह का लॉन्ग स्टे वीजा है, जिसके जरिए प्रोफेशनल्स फ्रांस में अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं या फिर उसे जारी रख सकते हैं। अगर आप भी फ्रांस जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो 'प्रोफेशन लिबेरेल वीजा' आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 'प्रोफेशन लिबेरेल वीजा' फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, डिजाइनर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव वर्कर और बिजनेस मालिकों के लिए फ्रांस जाने का सबसे बढ़िया रुट है। बस उन्हें साबित करना होगा कि उनका काम असली है और आर्थिक रूप से टिकाऊ है। वीजा के लिए आवेदकों को एक बढ़िया प्रोफेशनल प्लान जमा करना होगा, पर्याप्त फंड दिखाना होगा और अपने प्रोफेशन के लिए फ्रांसीसी नियमों को पूरा करना होगा। आइए इस वीजा के बारे में जान लेते हैं। इस वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आवेदकों को किसी फ्रेंच कंपनी से जॉब ऑफर लेने की जरूरत नहीं होती है। वे निम्नलिखित चीजों के लिए 'प्रोफेशन लिबेरेल वीजा' के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशन लिबरल रुट सैलरी वाले वर्क वीजा से अलग है। जिन जॉब्स में सैलरी मिलती हैं, उनके लिए जो वर्क वीजा दिया जाता है, वो तभी मिलता है, जब कंपनी की स्पांसरशिप हो। इसके साथ-साथ एक एंप्लॉयमेंट ऑफर और वर्क ऑथराइजेशन की भी जरूरत पड़ती है। 'प्रोफेशन लिबेरेल वीजा' का सीधा सा नियम है कि आवेदक को अपना खुद का प्रोफेशन या बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाना होगा। ये वीजा उन लोगों के लिए बेहतर है, जो पहले से ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं।

apollo TYRES
PASINDU SOORIYABANDARA 80

रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के युवा बल्लेबाज पासिंदु सूरियाबंदारा को बोल्ड कर उनका पहला टेस्ट शतक बनाने का सपना तोड़ दिया

कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत के पहली पारी में 503 रन के जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में 200 से पहले ही सात विकेट खो चुकी है और उस पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है। पसिंदु सोरियाबंदरा को छोड़कर कोई बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया है। तीसरे दिन जहां भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फील्डर भी श्रीलंकाई प्लेयर्स को उकसाने का प्रयास करते नजर आए हैं। सरफराज खान की धनंजय डी सिल्वा से कुछ ऐसी ही बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि सरफराज खान जब भी मैदान पर बल्लेबाजी या फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो वह शांत नहीं रहते हैं। इस बात को वह कई बार खुद भी कह चुके हैं। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन सरफराज शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट पर फील्डिंग करते समय काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने लगभग हर श्रीलंकाई बल्लेबाज से बात की है। जब मानव सुथार गेंदबाजी करने वाले थे, तब उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा से कहा कि ब्रो, कुछ नहीं है, ब्रो। तुम सीधे देखो ना, लेफ्ट और राइट साइड क्यों देख रहे हो? (लॉन्ग-ऑन और लॉन्ग-ऑफ की ओर इशारा करते हुए) तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो, ब्रो, डरो मत, खेलो। तुम कप्तान हो। तुम इसी का इंतजार कर रहे हो। यह सरफराज की धनंजय के आउट होने से पहले की बात है। इसके बाद मानव सुथार जब 35वां ओवर फेंक रहे थे, तो उस ओवर की पांचवीं गेंद पर धनंजय डी सिल्वा केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। वह सुथार का दूसरा शिकार बने।सुथार ने श्रीलंकाई कप्तान को मिडिल और ऑफ की तरफ अच्छी तरह से टॉस की गई गेंद फेंकी। टर्न लेती गेंद को धनंजय ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए जुरेल के ग्लव्स से डिफ्लेक्ट होकर स्लिप में फील्डर की तरफ गई। जहां खड़े राहुल ने कुछ अच्दी कोशिश करते हुए कैच को पूरा किया। यह काफी शानदार कैच रहा। धनंजय 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए।

कोलंबो टेस्ट में भारत ने दूसरे दिन 503/9 पर पारी घोषित कर श्रीलंका को बैकफुट पर धकेल दिया

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंकाई बल्लेबाज नहीं बल्कि मौसम है। भारत ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित करने के बाद दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के दो विकेट महज 8 रन पर झटक लिए। हालांकि, 25 अगस्त को बारिश की आशंका ने भारत की जीत की उम्मीदों पर चिंता बढ़ा दी है।भारत ने दूसरे दिन ध्रुव जुरेल के शानदार नाबाद शतक की बदौलत बड़ा स्कोर खड़ा किया। जुरेल ने 177 गेंदों पर 115 रन की पारी खेली और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ नाबाद लौटे। इससे पहले देवदत्त पडिक्कल ने भी 117 रन की बेहतरीन पारी खेलकर लगातार दूसरे टेस्ट में शतक जड़ा। कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।दिन की शुरुआत में भारत को सरांश जैन के रूप में झटका लगा, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत चोट के बावजूद बल्लेबाजी के लिए उतरे। पहले दिन कलाई में चोट लगने के बावजूद पंत ने 63 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने जुरेल के साथ सातवें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की, जिसने भारत को 500 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।भारत ने 503/9 पर पारी घोषित करने के बाद श्रीलंका को बल्लेबाजी का मौका दिया। मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और दूसरे ओवर में ही लाहिरु उदारा अपना विकेट गंवा बैठे। दिन की आखिरी गेंद पर प्रबाथ जयसूर्या भी आउट हो गए। इस तरह श्रीलंका ने सिर्फ 8 रन पर दो विकेट गंवा दिए और उसे पहली पारी में अभी 495 रन पीछे है।

हॉकी टीम की विफलता ने टीम चयन और कोर ग्रुप की निरंतरता पर गंभीर सवाल

विश्व कप में 51 साल बाद पदक जीतने का सपना लेकर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने में भी नाकाम रहने के बाद पूर्व दिग्गजों ने युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देने और उसी कोर ग्रुप के साथ लगातार खेलने पर सवाल उठाये हैं। अर्जेंटीना से 3 -5 से हारने के बाद भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी खत्म हो गई और इससे वे कमजोरियां भी उजागर हुई जो पेरिस ओलंपिक के बाद से लगातार चली आ रही थी। पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि धीमी शुरुआत, मौके गंवाने और डिफेंस में चूक से आगे यह समस्या और बड़ी है और इसका हल काफी पहले निकाला जाना चाहिये था। भारतीय टीम विश्व कप से पहले स्विटजरलैंड में मानसिक दृढता बढाने के लिये बूट कैंप में गई लेकिन टूर्नामेंट में दबाव का सामना नहीं कर सकी। ड्रैग फ्लिकर और कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर अधिक निर्भरता का खामियाजा भुगतना पड़ा जबकि वह पूरी तरह फिट नहीं थे। मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह जैसे सीनियर अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके।

SUKHJEET
34
ODISHA

पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास लेने वाले गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने जूनियर खिलाड़ियों को समय पर मौके नहीं दिये जाने का हवाला देते हुए से कहा ,“सीनियर खिलाड़ियों के जाने के बाद उनकी जगह कौन लेगा। क्या हमने दूसरी जमात तैयार की है। लॉस एंजिलिस ओलंपिक में दो ही साल बचे हैं और उससे पहले करीब तीस अंतरराष्ट्रीय मैच ही होंगे। क्या ओलंपिक के लिये इससे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। नहीं।”उन्होंने कहा ,“ विश्व कप की टीम में भी भी वही कोर खिलाड़ी हैं जबकि मनमीत सिंह, आमिर अली, रोशन कुजूर, तालेम प्रियब्रत, रोहित, अर्शदीप जैसे कई प्रतिभाशाली जूनियर इंतजार ही कर रहे हैं।” पूर्व ओलंपियन जगबीर सिंह ने कहा कि चयन के कुछ फैसले बेहतर हो सकते थे। उन्होंने कहा ,“ जूनियर खिलाड़ियों को सही समय पर मौके मिलने चाहिये और चयन के कुछ फैसले बेहतर हो सकते थे। तैयारी ओलंपिक से ओलंपिक की होनी चाहिये। कोचिंग स्टाफ ने अनुभव को ही तरजीह दी जो काम नहीं आया। भारत के पास यह सर्वश्रेष्ठ मौका था लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता नहीं दिखी। हर दस मिनट में डिफेंस चरमरा रहा था।”

लंदनः 2 लाख किराए में सिर्फ 24 गज का घर

लंदन दुनिया के ड्रीम प्लेसेस में से एक है. इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है. दुनिया के कई अमीर और सफल लोगों का इस शहर से खास रिश्ता रहा है. लोग यहां बसने का सपना लेकर आते हैं. लंदन में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं. वहां वे कमाते हैं, सेटल हैं और अपनी जिंदगी बुन रहे हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला दिखा रही है कि लंदन में 2 लाख भारतीय रुपये किराए में कैसा आशियाना मिलता है. ⊙

लोगों ने दिया ऐसा प्यार कि बन गई 'इंडिया की बेबी'

मासूम टिंकल ने सिखाया बड़ा सबक!

अरुणाचल प्रदेश की 4 साल की कार्गा टिंकल ने लोगों से कहा था कि उन्हें 'चाइनीज' नहीं, भारतीय कहा जाए. वीडियो वायरल हुआ तो देशभर से उसे प्यार मिला और अब लोग उसे 'इंडिया की बेबी' कह रहे हैं.

एक मासूम बच्ची की शिकायत थी कि लोग उसे उसकी शक्ल देखकर 'चाइनीज' कहते हैं. जबकि वो है तो भारतीय. उसने अपनी यही शिकायत दुनिया के सामने रख दी. फिर क्या था, सोशल मीडिया पर देशभर से उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा. लोग उसे 'इंडिया का बेबी' कहने लगे. हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर की रहने वाली 4 साल की कार्गा टिंकल गोंगो की. उम्र भले सिर्फ 4 साल है, लेकिन उसकी एक छोटी-सी शिकायत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये कि आखिर किसी भारतीय बच्चे को लोगों को ये क्यों समझाना पड़ रहा है कि वो भारतीय है? टिंकल के पहले वीडियो में उसने बेहद मासूमियत से कहा था कि लोग उसे चाइनीज कहते हैं, लेकिन 'हम लोग इंडियन हैं'.उसने कहा कि जब कोई उसे चाइनीज कहता है तो उसे दुख और गुस्सा आता है. फिर उसने लोगों से बस इतनी-सी गुजारिश की- 'हमको इंडियन बोलो.' इस वीडियो को अबतक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुका है. इस वीडियो के पीछे एक असली घटना भी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिंकल अपनी मां के साथ आइसक्रीम खरीदने गई थी और वहां हिंदी में बात कर रही थी. इसी दौरान किसी ने उन्हें 'चाइनीज बच्चे' कह दिया. ⊙

असली सवाल अभी भी बाकी है

इस कहानी को सिर्फ एक 'क्यूट वायरल वीडियो' मानकर आगे बढ़ जाना शायद सबसे आसान बात होगी. लेकिन असली एंगल इससे बड़ा है. टिंकल को देश ने प्यार देकर अपना लिया, लेकिन उसे पहले अपनी भारतीय पहचान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी बात किसी बहस, भाषण या राजनीतिक नारे से नहीं आई थी. वो सिर्फ 4 साल की बच्ची थी, जो शायद इतनी-सी बात जानती थी कि उसका चेहरा उसकी नागरिकता तय नहीं करता. लेकिन ये बात अभी भी बड़े-बड़े लोगों को समझ में क्यों नहीं आई. टिंकल को अब लोग 'इंडिया का बेबी' कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

40 की उम्र में 1.05 करोड़ जुटाकर रिटायरमेंट की तैयारी

FLIGHT WAVE

नेहा का दावा है कि उन्होंने अपनी सैलरी को इस तरह मैनेज किया कि महज 32 साल की उम्र में उनके पास करीब 1.05 करोड़ रुपये की सेविंग हो गई. खास बात यह है कि उनकी मंथली सैलरी 1.20 लाख रुपये है. फिर भी वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं. अब उनके सामने अगला सवाल है- क्या वह 40 से 42 साल की उम्र में जॉब छोड़कर रिटायर हो सकती हैं? नेहा ने अपनी कमाई को किसी एक जगह लगाने के बजाय अलग-अलग ऑप्शन में बांट दिया. वह 2019 से लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं. आज उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो करीब 25 लाख रुपये का हो चुका है. इसके अलावा उन्होंने स्टॉक्स में करीब 38 लाख रुपये लगाए हैं. 2023 में उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी में 11.7 लाख रुपये का निवेश किया था. उनका प्रोविडेंट फंड करीब 24 लाख रुपये का हो चुका है, जबकि बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपये अलग से जमा हैं. ⊙

भारतीय महिला ने दिखाया ब्रिटेन में मजदूरी का फर्क

20 मिनट की मेहनत और ₹12 हजार फीस

भारत और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के वर्क कल्चर में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर इसी अंतर को दिखाता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है. इंग्लैंड में रहने वाली एक भारतीय महिला ने छत के किनारे बने बारिश के पानी वाले ड्रेन की सफाई का बिल शेयर किया तो सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. वजह सिर्फ 92 पाउंड, यानी करीब 12 हजार रुपये का खर्च नहीं था, बल्कि यह भी था कि सफाई का पूरा काम कथित तौर पर महज 20 मिनट में खत्म हो गया. मंजू शेखावत परमार ने वीडियो में बताया कि उनके घर की छत के किनारे बने रेनवॉटर ड्रेन में सूखे पत्ते और काफी गंदगी जमा हो गई थी. इसे साफ करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया. वीडियो में कर्मचारी सीढ़ी लगाकर छत तक पहुंचता है. इसके बाद वह ड्रेन की सफाई शुरू करता है. अंदर जमा सूखे पत्ते और गंदगी निकालकर एक बाल्टी में इकट्ठा करता है. फिर वह घर के दूसरे हिस्से में जाकर वहां का ड्रेन भी साफ करता है.बस करीब 20 मिनट में यह पूरा काम हो गया और इसके बदले उसे 92 पाउंड, यानी करीब 12 हजार रुपये मिल गए. अब इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट भी आए. कुछ लोगों ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के सर्विस चार्ज में काफी बड़ा अंतर है. विदेशों में लेबर और सर्विस की कीमतें अलग होती हैं. ⊙

सस्पेंस और क्राइम से बढ़ा रोमांच

करीना कपूर-पृथ्वीराज की 'दायरा' का नया पोस्टर रिलीज

बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री करीना कपूर खान और लोकप्रिय अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' का नया पोस्टर सामने आया है। इस नए विजुअल ने फिल्म की सस्पेंस से भरी दुनिया की एक गहरी झलक पेश की है। निर्देशक मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी मुख्य कहानी के रहस्य को छिपाकर रखते हुए दोनों मुख्य अभिनेताओं के बीच के पेचीदा संबंधों की ओर इशारा करती है।जारी किए गए पोस्टर में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक-दूसरे से विपरीत दिशा में पीठ सटाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच पुलिस की येलो इन्वेस्टिगेशन टेप की परतें लगी हुई हैं, जो किसी अपराध की ओर सीधा इशारा करती हैं। इसके अलावा पृष्ठभूमि में एक अज्ञात और धुंधला चेहरा भी नजर आ रहा है, जो पोस्टर के सस्पेंस को और गहरा बनाता है। दोनों अभिनेताओं का यह रुख दिखाता है कि उनके किरदार शायद किसी एक ही आपराधिक घटना को अपने-अपने अलग नजरिए से देख रहे हैं।यह पोस्टर कहानी का खुलासा किए बिना ही दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। पुलिस टेप, ओझल चेहरा और मुख्य पात्रों के बीच की दूरी यह सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों की जिंदगियां किस तरह एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे यह जांच आगे बढ़ेगी। फिल्म 'दायरा' के माध्यम से करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिखाई देने वाली है। दोनों ही मंझे हुए कलाकारों को एक थ्रिलर ड्रामा में आमने-सामने देखना दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ निर्देशक मेघना गुलजार अपनी पुरानी प्रोडक्शन टीम के साथ वापस लौटी हैं, जिनके साथ वे पहले भी कई बेहतरीन और विषय-प्रधान फिल्में बना चुकी हैं।यह क्राइम थ्रिलर सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है, जिसकी पटकथा लेखन में मेघना गुलजार के साथ अन्य अनुभवी सह-लेखकों का योगदान रहा है। 'दायरा' 18 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए निर्धारित है। जल्द ही पेश किए जाने वाले आधिकारिक ट्रेलर से दर्शकों को इस उलझी हुई क्राइम स्टोरी की परतें समझने का मौका मिलेगा।

लखनऊ जिला न्यायालय के पास 12 अवैध चैंबर हटाने का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की याचिका पर दखल से किया इनकार

लखनऊ जिला न्यायालय के आसपास बने 12 कथित अवैध चैंबरों को हटाने की कार्रवाई अब आगे बढ़ सकेगी।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि पद या पेशे के आधार पर अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त रखना कानून और व्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है।

लखनऊ जिला न्यायालय के आसपास सार्वजनिक रास्तों और उपयोगिता भूमि पर बने कथित अवैध निर्माणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि कोई व्यक्ति वकील हो या बार एसोसिएशन का पदाधिकारी, इस आधार पर अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।मामला लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के आसपास बने कई कथित अवैध चैंबरों से जुड़ा है। इनमें से 12 चैंबरों को हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए लखनऊ नगर निगम को करीब 72 कब्जेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इन सभी को अपना पक्ष रखने और संबंधित जमीन तथा निर्माण पर वैध अधिकार साबित करने का अवसर दिया जाना था।हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि कब्जेदार जमीन और निर्माण को लेकर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर पाते हैं तो कानून के मुताबिक अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम की ओर से कार्रवाई की तैयारी शुरू होने और 30 अगस्त तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित होने के बाद कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने याचिकाकर्ताओं से निर्माण की वास्तविक स्थिति और उसके स्थान को लेकर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि मुख्य सड़क के आसपास इस तरह के ढांचे कैसे खड़े कर दिए गए।सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले अवैध निर्माण करना और बाद में बार एसोसिएशन में पद होने का हवाला देकर उसे बचाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सार्वजनिक रास्तों और न्यायालय परिसरों को अतिक्रमण से मुक्त रखना बेहद जरूरी है।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाला ने प्रभावित वकीलों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने और विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता।जस्टिस विक्रम नाथ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं उस क्षेत्र की स्थिति देखी है। उन्होंने बताया कि किस तरह सड़कें घेर ली गई थीं और यातायात प्रभावित हो रहा था। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण को लेकर न्यायपालिका गंभीर है।अब लखनऊ नगर निगम को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। जिन कब्जेदारों के पास वैध दस्तावेज या अधिकार नहीं होंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह संदेश भी गया है कि न्यायालय परिसर और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किसी पेशे या पद की आड़ में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

100 से ज्यादा युवाओं ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास का घेराव किया

लखनऊ में मंगलवार को 100 से ज्यादा युवाओं ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास का घेराव किया। अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। सुबह 10 से 11 बजे तक करीब एक घंटे तक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बृजेश पाठक जब घर से बाहर निकले तो अभ्यर्थी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ युवाओं ने उनके पैर भी छुए। अभ्यर्थियों ने कहा- 'सर, नौकरी चाहिए।' इसके बाद डिप्टी सीएम ने तुरंत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्ष से फोन पर बात की। अभ्यर्थियों की मांग पर समाधान निकालने के लिए कहा। अभ्यर्थियों ने बताया- 2016 के बाद से लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले भी वे UPSSSC मुख्यालय के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कई जगह बिना लाइब्रेरी साइंस की डिग्री वाले लोगों से काम कराया जा रहा है, जबकि संबंधित डिग्री लेने वाले युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने PET-2025 के आधार पर लाइब्रेरियन के पदों पर नई भर्ती निकालने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल अमित ने बताया कि वे लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती की मांग कर रहे हैं। 14 मई, 2 जून और 19 जून 2026 को भी अभ्यर्थियों ने पिकप भवन का घेराव किया था। वहां अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता और कर्मचारी ही उनसे बात करते हैं। अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि लाइब्रेरियन के 362 पदों की अधियाचना मिल चुकी है। इसके बावजूद हर बार अगले महीने भर्ती निकालने की बात कहकर मामला टाल दिया जाता है। पिछली बार 2016 में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती हुई थी। तब से युवा लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई और डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कुछ लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया है

AIIA
AIIA
AIIA
AIIA
AIIA
AIIA
AIIA

स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना रशीदी ने कहा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है, तो उसे मना नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर लड़की को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, स्कूल के नियम उसके ऊपर थोपे नहीं जा सकते। एक वीडियो जारी करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह फैसला एक स्कूली छात्रा के हिजाब के याचिका को लेकर दिया गया। उसने कहा कि मैंने 10वीं तक इसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई की है, अब 11वीं में मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है। तो यह कौन सा स्कूल का यूनिफॉर्म नियम है, जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है? क्या हाईकोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है, तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया?' साजिद रशीदी ने कहा, 'दूसरी बात यह, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल अपने मनमाने तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या यह ठीक है? क्या यह इंसान की आजादी पर का हनन नहीं है?' मौलाना ने कहा, 'मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर ये नहीं थोपा जा सकता कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। कुछ लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से दुश्मनी है। हिजाब के नाम को लेकर इस तरह की बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए।' साजिद रशीदी ने आगे कहा, 'मैं कोर्ट से भी और तमाम स्कूल के जो संस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर लड़की अपनी मर्जी से कोई चीज पहनना चाहती है तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लड़कियों की ड्रेस पर बात करते हैं कि आज कल इस तरह से लड़कियां अधनंगी हालत में घूमती हैं, तो आप लोगों का सबसे पहले जवाब यही होता है कि यह तो उनकी अपनी आजादी है।

नगर निगम में 243 भैंसों की नीलामी के दौरान हंगामा और सड़क जाम करने के मामले में FIR

लखनऊ नगर निगम में 243 भैंसों की नीलामी के दौरान हंगामा और सड़क जाम करने के मामले में FIR दर्ज हुई है। लालबाग पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा समेत 11 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी। आरोपियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन, नारेबाजी, सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक रास्ता रोकने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में 243 भैंसों की नीलामी चल रही थी। इसी दौरान अनीस रजा समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और नीलामी प्रक्रिया रोकने की कोशिश की। विरोध-प्रदर्शन करके मेन रोड जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। कई प्रदर्शनकारियों को टांगकर ले गई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर एक साथ मिलकर अपराध करने, गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा बनने, सरकारी आदेश का उल्लंघन, सार्वजनिक रास्ता रोकने और शांति भंग करने के आरोप में BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण आम लोगों को परेशानी हुई। FIR में अनीस रजा, सलीम, राजेश पांडेय उर्फ बिल्लू, अतुल यादव, तुषार श्रीवास्तव, कुलदीप पासवान, रोहित यादव, बावी धानुक, अबुल हाजिम, सुजीत और विवेक सिंह को नामजद किया गया है।

वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ 2020 से 2026 तक 866 अस्पतालों पर कार्रवाई

योगी सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज में लापरवाही, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं पर लगातार आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2020 से 2026 तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें सबसे अधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया। वहीं 17 अस्पतालों में विशेषता को डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। इसके अलावा 140 अस्पतालों पर पेनाल्टी की कार्रवाई करते हुए साढ़े आठ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनसे अब तक 4 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने की धनराशि वसूली गई है। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के गुणवत्तापूर्ण इलाज को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में लापरवाही पर 318 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया।

मायावती का बड़ा ऐलान: विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्वीट के जरिए प्रेस रिलीज साझा करते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन तीनों राज्यों में बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अच्छा परिणाम लाने का संकल्प लिया गया है। यह निर्णय लखनऊ कार्यालय में हुई पार्टी संगठन की लंबी बैठक के बाद लिया गया। बैठक में मायावती ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देगी। यूपी और उत्तराखंड में उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता बरती जाएगी तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। पंजाब में पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने पर विशेष फोकस करेगी। मायावती ने 9 अक्टूबर को बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती देशभर में बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया। साथ ही 15 जनवरी 2027 को अपने जन्मदिन के मौके पर जनकल्याणकारी दिवस आयोजित करने का फैसला लिया गया। इस दौरान पिछली बार से अधिक आर्थिक सहयोग जुटाया जाएगा ताकि अंबेडकरवादी विचारधारा का प्रसार हो और बसपा आंदोलन मजबूत हो। बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और अपना मनोबल ऊंचा रखें। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा यह प्रचार किया जाएगा कि अकेले लड़ने से सीटें और वोट प्रतिशत कम होंगे। ऐसे में साम, दाम, दंड और भेद जैसी सभी हथकंडों का डटकर सामना करना होगा। पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों से त्रस्त है, इसलिए बसपा को वहां बदलाव का विकल्प बनना है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसमें बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया था। इसके बाद पार्टी लगातार अकेले चुनाव लड़ रही है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली थी जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद नहीं जीत सका। मायावती के इस ऐलान से साफ है कि बसपा तीनों राज्यों में स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत आजमाएगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने, ईमानदार उम्मीदवार चुनने और जनाधार बढ़ाने पर जोर देगी। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की रणनीति को स्पष्ट करता है।

उन्नाव के शुक्लागंज में किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बैठक

प्रमुख मुद्दों पर निर्णायक आंदोलन और सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया

उन्नाव के शुक्लागंज में किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई। प्रदेश सचिव कैप्टन राहुल तिवारी के आवास पर हुई इस बैठक में जनपद और आम जनता से जुड़े छह प्रमुख मुद्दों पर निर्णायक आंदोलन और सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने की। इसमें जिले के संगठन मंत्री लल्लन शर्मा और शुक्लागंज नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में छह प्रमुख मांगें उठाई गईं। इनमें ट्रांस गंगा सिटी के बंद पड़े बिजलीघरों को चालू कर शुक्लागंज सहित जिले के अन्य गांवों और कस्बों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ट्रांस गंगा सिटी के किसानों को जल्द विकसित प्लॉट उपलब्ध कराने, जिले में बूचड़खानों को बंद कर प्रदूषण से राहत दिलाने की मांग की गई। अन्य मांगों में उत्तर प्रदेश में भेदभाव रहित व्यवस्था लागू कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना, महिलाओं को तीन हजार रुपये और युवाओं को चार हजार रुपये प्रतिमाह देना शामिल है। राशन वितरण में कथित कटौती को रोकने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने उन्नाव की धार्मिक, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लव-कुश, माता सीता और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी इस धरती पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, और यह महान कवि मौलाना हसरत मोहानी की जन्मस्थली भी है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे जनपद में बिजली, बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं जिले की पहचान को प्रभावित कर रही हैं। प्रदेश सचिव कैप्टन राहुल तिवारी ने बताया कि बैठक में उठाए गए मुद्दे केवल किसानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे आम जनता के अधिकार और जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान होने तक गांव-गांव और अलग-अलग स्थानों पर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिला संगठन मंत्री लल्लन शर्मा ने घोषणा की कि जनपद में किसान कार्यालय खोलकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने ट्रांस गंगा सिटी में मौजूद बिजलीघरों की स्थिति पर सवाल उठाए। 120 केवीए क्षमता वाले बिजलीघर मौजूद हैं, जबकि पांच बिजलीघर बंद पड़े हैं और उनकी मशीनरी जंग खा रही है। इसके बावजूद शुक्लागंज की जनता बिजली संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर किसान आंदोलन निर्णायक संघर्ष करेगा। बैठक में पदाधिकारियों ने छहों मुद्दों को लेकर किसानों और आम जनता को साथ जोड़कर चरणबद्ध आंदोलन चलाने पर जोर दिया।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की रोजाना भ्रष्टाचार की पोल खुल रही

लोकार्पण के 13वें दिन से धंस रहा कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे रोज कहीं-न-कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। कहीं सड़क दरक रही है तो कहीं पर सड़क पटरी और किनारे की मिट्टी धंस जाती है। सोमवार को झाऊखेड़ा के पास बने उस रेस्ट एरिया की भी सर्विस रोड धंस गई जहां पर एनएचएआई ने 13 जुलाई को लोकार्पण के समय हाईटेक तकनीक वाले एक्सप्रेसवे की तस्वीरों और वीडियो की प्रदर्शनी लगाई थी। 4200 करोड़ की लागत वाले कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हालत खस्ता है। उन्नाव-लखनऊ के बीच 45 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड हिस्से में अब तक 2500 से अधिक पैचवर्क, 170 जगह पर 10 से 50 मीटर तक उखाड़कर सड़क को दोबारा बनाया गया है। वहीं दोनों तरफ 80 से अधिक स्थानों पर सड़क पटरी और किनारे की मिट्टी धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। सोमवार को किलोमीटर संख्या 51.3 के सामने लखनऊ-कानपुर लेन पर झाऊखेड़ा गांव के पास बने रेस्ट एरिया की सर्विस रोड में 40 मीटर लंबी दरार आ गई। यह वही स्थान है जहां से 13 जुलाई को लोकार्पण के समय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा तीनों जिलों के जनप्रतिनिधियों को एनएचएआई ने इस एक्सप्रेसवे को हाईटेक और विदेशी तकनीक से बनाने के दावे किए थे।

सोडियम सल्फाइट से बासी खोये को बना रहे थे ताजा, डेयरी बंद, लाइसेंस निलंबित

रक्षाबंधन पर खोया (मावा) से निर्मित मिठाइयों की खपत को देखते हुए जनपद में मिलावट का बाजार गर्म हो गया है। हफ्तों पहले तैयार किए गए बासी खोये को ताजा दिखाने के लिए प्रतिबंधित पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। सफीपुर की डेयरी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिबंधित पाउडर सोडियम सल्फाइट का खोये में इस्तेमाल पकड़ा है। इस पर लाइसेंस निलंबित कर दुकानदार को नोटिस जारी किया है। अग्रिम आदेशों तक डेयरी बंद करा दी है। 87 हजार रुपये का खोया भी नष्ट करा दिया। आठ किलो पाउडर सीज कर दिया गया। सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। सहायक खाद्य आयुक्त प्रियंका सिंह के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में रुचि बाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद, आशीष कुमार वर्मा ने सफीपुर में मेसर्स सागर डेयरी में सोमवार को जांच की। यहां पर भारी मात्रा में बनाया जा रहा खोया मिला। साथ ही सोडियम सल्फाइट पाउडर भी रखा था। खोया जांच में पाउडर की मिलावट की पुष्टि हुई। इस पर अधिकारियों ने तैयार 87 हजार कीमत का 290 किलो खोया नष्ट करा दिया। 960 रुपये का आठ किलो पाउडर सीज करके डेयरी बंद करा दी। इसके अलावा 21600 रुपये का 360 लीटर दूध भी नष्ट कराया गया। 12 हजार रुपये का 15 किलो घी भी सीज किया है। यहां से खोया, पाउडर, घी व दूध का सैंपल भी लिया गया।

दो बहनों ने होमगार्ड की पिटाई कर दी जब वह चौराहे पर यातायात व्यवस्था को संभाल रहा था

उन्नाव में तिराहे पर जाम की स्थिति देख यातायात संभाल रहे होमगार्ड में ई रिक्शा को हटाने की कोशिश की। इस दौरान ई रिक्शा चालक के साथ वाद-विवाद हो गया। मौके पर चालक और ई रिक्शा में बैठी दो बहनें होमगार्ड के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगी। वायरल वीडियो में हाथ और डंडे से पिटाई करते दिखाई पड़ रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पर पुलिस का जवाब आया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि थाने में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर लखनऊ राजधानी मार्ग पर पोनी गांव तिराहा काफी व्यस्त रहता है। तिराहे के आसपास सैकड़ो की संख्या में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर ही गंगा घाट कोतवाली स्थित है। ई-रिक्शा के कारण यहां पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए होमगार्ड सुरेश चंद्र की ड्यूटी लगाई गई थी। जाम की स्थिति को देखते हुए होमगार्ड सुरेश चंद्र ई-रिक्शा को हटाने को कहा। इस पर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया। जो इतना बढ़ गया कि ई रिक्शा चालक और बैठी दो लड़कियां होमगार्ड से अभद्रता करने लगी। होमगार्ड सुरेश चंद्र की डंडे से पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सामने आया है। इस संबंध में गंगा घाट थाना पुलिस में बताया कि 22 अगस्त की घटना है। गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पोनी तिराहा राजधानी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होमगार्ड सुरेश चंद्र को तैनात किया गया था। तिराहे पर ई रिक्शा के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसे सुरेश चंद्र में हटाने के लिए कहा। इस पर ई रिक्शा चालक रंजीत पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र से बहस हो गई। इस दौरान परीक्षा में बैठी सारिका धीमान पुत्री स्वर्गीय रमेश और नैंसी पुत्री स्वर्गीय रमेश निवासीगण मोहल्ला बिंदा नगर, पुलिस चौकी वाली गली शुक्लागंज थाना गंगा घाट ने आक्रोशित होकर होमगार्ड सुरेश चंद्र के साथ अभद्रता करने लगी। इसके साथ ही सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। होमगार्ड सुरेश चंद्र की लिखित तहरीर पर गंगा घाट थाना में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351, 312(1), 132 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) ने सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया

उन्नाव में मानदेय भुगतान में कथित भेदभाव और देरी के विरोध में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) ने मंगलवार शाम सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले हुए प्रदर्शन में करीब 200 सीएचओ शामिल हुए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। सीएचओ ने एएमएस (अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम) आधारित मानदेय भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि इस प्रणाली के तहत मानदेय भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं, जिससे उनमें असंतोष है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनका मानदेय भी अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की तरह समान प्रक्रिया के तहत समय पर जारी किया जाए। उनका कहना था कि समान विभागीय व्यवस्था के तहत काम करने के बावजूद मानदेय भुगतान में अंतर नहीं होना चाहिए। धरने की सूचना मिलने पर सीएमओ डॉ. अजय कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीएचओ प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएचओ ने मानदेय भुगतान में कथित भेदभाव और प्रक्रियागत दिक्कतों को अधिकारियों के सामने रखा। वार्ता में डीपीएम इंतजार अहमद सिद्दीकी और एसीएमओ डॉ. जेआर सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीएचओ को आश्वासन दिया कि मानदेय भुगतान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही बताया कि मंगलवार को ही मानदेय भुगतान से संबंधित प्रक्रिया पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी। सीएमओ डॉ. अजय कुमार शर्मा ने दोहराया कि मानदेय के मामले में किसी भी सीएचओ के साथ भेदभाव नहीं होगा और उनकी समस्या का नियमानुसार समाधान कराया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सीएचओ ने धरना समाप्त कर दिया। संगठन के जिला महामंत्री प्रशांत गुप्ता और जिलाध्यक्ष राजेश कुमार समेत बड़ी संख्या में सीएचओ मौजूद रहे। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग समय पर और समान प्रक्रिया के तहत मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराना है। भविष्य में भुगतान संबंधी समस्या आने पर संगठन आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।

बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर उसे घायल कर दिया, अस्पताल में मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के चक जमालपुर गांव में एक युवक ने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आए अपने छोटे भाई पर धारदार कृषि उपकरण से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई की अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपी बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, रविवार रात चक जमालपुर गांव निवासी किशन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर रहा था। घर में विवाद और शोर सुनकर उसका 29 वर्षीय छोटा भाई दिलीप बीच-बचाव करने पहुंचा। बताया जा रहा है कि छोटे भाई का बीच में आना किशन को नागवार गुजरा। विवाद बढ़ने पर उसने पास में रखे हंसिया से दिलीप पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन गंभीर रूप से घायल दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ पुरवा अरविंद चौरसिया के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब के नशे में अपने परिवार के साथ मारपीट कर रहा था। इसी दौरान दिलीप ने बीच-बचाव की कोशिश की और विवाद के बाद उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर आरोपी बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर घटना की जांच की जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

वाराणसी श्रेया हत्याकांड का बड़ा खुलासा
22 लाख के लालच में रची गई हत्या की साजिश

वाराणसी के श्रेया उपाध्याय हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी पुनीत मिश्रा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर 22 लाख रुपये के लालच में हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रेया उपाध्याय की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में सामने आया है कि आरोपी ने 22 लाख रुपये के लालच में श्रेया की हत्या कर दी थी। घटना 18 अगस्त की है। दरअसल, रोहनिया के बच्छांव पश्चिमपुरा में किराए के मकान में 22 वर्षीय श्रेया उपाध्याय रहती थी। वह राजातालाब के मरुई की रहने वाली थी। उसके कथित प्रेमी विवेक चौबे और उसके दोस्त पुनीत मिश्रा पर हत्या का आरोप लगा। मामला सामने आने के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। घटना में आरोपी पुनीत को एसओजी और राजातालाब पुलिस ने जक्खिनी रोड से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। पुनीत ने गिरफ्तारी के बाद श्रेया हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा किया। उसने 22 लाख रुपये के लालच में हत्या की बात स्वीकार की। पुनीत ने पुलिस को बताया कि विवेक ने उसे श्रेया की हत्या के बाद 22 लाख रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, श्रेया की हत्या के पीछे कारण क्या था, पुनीत ने इस जानकारी से इनकार किया है। पुनीत मूल रूप से मऊ के हलधरपुर थाना क्षेत्र के मिसरौली बकुची के डाड़ीडीह अरदौना का रहने वाला है। पुनीत ने बताया कि वह रांची में था। विवेक ने उसे फोन कर श्रेया के बारे में बताया। विवेक ने श्रेया हत्याकांड में शामिल होने पर पैसे का लालच दिया। उसने कहा कि अगर वारदात में साथ देगा तो हत्या के तुरंत बाद पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद विवेक ने साजिश के तहत पुनीत का रांची से वाराणसी के लिए रेल टिकट कराया। पुनीत वाराणसी पहुंचा। 17 अगस्त की रात ही पुनीत और विवेक बच्छांव पश्चिमपुरा के किराए के कमरे में आ गए थे। दोनों ने हत्या की फुलप्रूफ प्लानिंग कर ली थी। पुनीत ने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त की सुबह जैसे ही श्रेया को लेकर विवेक कमरे पर आया, वह पहले ही चाकू लेकर तैयार खड़ा था। श्रेया के कमरे के भीतर घुसते ही विवेक ने उसका पीछे से गला पकड़ लिया। इसके बाद पुनीत ने उसके पेट में चाकू मार दिया। गला कसकर पकड़े जाने से श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद उसके गले पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने श्रेया के शव खींचकर बाथरूम में रख दिया। श्रेया की हत्या के बाद विवेक पैसा लाने की बात कहकर निकल गया। 20 मिनट तक कमरे पर पुनीत ने विवेक का इंतजार किया। वह 22 लाख रुपये की आस लगाए हुए था। इस दौरान उसने विवेक को फोन भी मिलाया। 20 मिनट बाद विवेक का फोन बंद हो गया। बाद में उसे लगने लगा कि कहीं इस मामले में वह पकड़ न लिया जाए। इसके बाद उसने अस्सी पर एक होटल में कमरा बुक किया। वहां कुछ घंटे रुका रहा। इस दौरान विवेक से संपर्क करने की कोशिश की। संपर्क नहीं हो पाने के बाद पुनीत रांची की बस पकड़ कर निकल गया। एसओजी प्रभारी गौरव सिंह के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान घटनास्थल के पास एक कैब दिखी। उस कैब में पुनीत बैठता दिखाई दिया। पुलिस ने कैब का पीछा किया। कैब चालक प्रयागराज का रहने वाला है। पुनीत ने ऑनलाइन कैब बुक की थी। इस कारण उसका नंबर ड्राइवर के पास था। पुलिस ने पुनीत का नंबर हासिल करने के बाद कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई। इसमें पता चला कि पुनीत और विवेक के बीच पिछले कुछ दिनों में लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस का शक इसके बाद पुनीत पर गहराया। इस बीच पुनीत ने अपना सिम तोड़कर फेंक दिया। पुलिस ने उसके नजदीकी लोगों के जरिए उसका पीछा शुरू किया। सोमवार तड़के आरोपी के बाइक से वाराणसी आने की जानकारी मिली। जक्खिनी मार्ग पर जमुनीपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान आरोपी दिखा। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह जख्मी हो गया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा, घटना में प्रयुक्त बाइक, एक आई-फोन बरामद किया गया। बरामद बाइक विवेक की दी हुई बताई गई है।

यूपी में 3572 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा

यूपी में कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित युवाओं को मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3446 पदों, जबकि मंडी परिषद में मंडी सचिव के 126 पदों पर चयन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। दोनों विभागों के चयनित कार्मिकों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर सीएम योगी ने सबसे पहले नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी। फिर कहा कि आज के दिन पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पूरी करना अपने आप चैलेंज है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सभी का चयन किया जाए, यह चैलेंज है, लेकिन हमारे भर्ती आयोग यह सफल रूप से कर रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार की यह उपलब्धि है। 9.30 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजा और महाभारत का खानदान वसूली पर निकल पड़ता था। युवाओं का समय खराब होता था। भर्ती के जिम्मेदार पदों पर भ्रष्ट लोगों को बैठा दिया गया था। हमने आते ही कहा था कि गड़बड़ी हुई तो माफिया की कमर तोड़ेंगे, हमने करके दिखाया। अगले छह महीने के अंदर एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यूपी के अंदर कभी ऐसी कल्पना नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने कहा कि परीक्षा एक महीने के अंदर कराइए। अधिकारी बोले संभव नहीं है। हमने कहा कुर्सी छोड़िए हम करा लेंगे। आज 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम यानी एक महीने से कम समय में परीक्षा पूरी हो रही है।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर संतों की बैठक में हंगामा

अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावे के कथित विवाद को लेकर संत समाज की बैठक में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया, जब बैठक स्थल पर अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस के जवान पहुंच गए। संतों ने आरोप लगाया कि उन्हें राम मंदिर चढ़ावे के कथित विवाद पर बैठक और चर्चा करने से रोका गया। बैठक स्थल से मीडिया कर्मियों को बाहर किए जाने को लेकर भी संतों और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति बनी। पुलिस और एलआईयू की तैनाती से संतों में नाराजगी और बढ़ गई। vकंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संतों ने राम मंदिर चढ़ावे के कथित घोटाले की उच्चस्तरीय जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग उठाई। संतों ने चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संतों का आरोप है कि एसआईटी की जांच में छोटे आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जबकि बड़े लोगों को बचा लिया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। बैठक के बाद कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज चढ़ावे के कथित विवाद की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो एक लाख संतों के साथ अयोध्या पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। संत समाज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी कर रहा है। संतों ने कहा कि वे रामलला का दर्शन कर चढ़ावे के कथित विवाद को लेकर भगवान श्रीराम से क्षमा मांगेंगे। संतों ने आरोप लगाया कि अयोध्या में चढ़ावे के विवाद पर बोलने से उन्हें रोका जा रहा है। बैठक के दौरान पुलिस और एलआईयू की मौजूदगी को लेकर भी संतों ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि संत समाज की बैठक में पुलिस की इस तरह मौजूदगी उचित नहीं है। बैठक में शामिल संतों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई।

बसपा विधायक शाहनवाज राणा के नौ ठिकानों पर की गई छापेमारी

मुजफ्फरनगर के पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा के न्यू राणा हाउस पर ईडी का छापा पड़ा था, इसी मामले में गाजियाबाद में भी सुधा स्टील के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। पूर्व बसपा विधायक के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में नौ ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान कुल 3.6 करोड़ रुपये नकद ज़ब्त किए गए हैं। ये सारे कैश सूटकेस में बंद किए गए थे। रेड के बाद सभी परिसर बंद कर दिए गए हैं। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत तरीके से लाभ लेने का है पूरा मामला। असली सामान की आवाजाही के बिना ही फर्जी इनवॉइस, बिल के जरिए बोगस आईटीसी बनाने और उसे आगे बढ़ाने का आरोप। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर सर्कुलर लेनदेन, रकम को तेजी से लेयरिंग करके बांटने, फर्जी कंपनियों के जरिए कैश निकालने का भी खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी की थी। छापेमारी में इस नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं और साथ ही करोड़ों की रकम बरामद हुई है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने सोमवार को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े नेटवर्क की जांच के सिलसिले में बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा व उनके परिजनों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने मुजफ्फरनगर स्थित राणा हाउस और गाजियाबाद की फर्म से तीन करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई है। बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा वेस्टर्न यूपी की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं। राणा ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतकर विधायक भी बने, लेकिन बाद में वे राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ गए। इसके बाद फिर नवंबर 2025 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी (काशीराम) की सदस्यता ली थी। बता दें कि उनके भाई कादिर राणा पूर्व सांसद और नूर सलीम राणा भी पूर्व विधायक रहे हैं।

देश में नंबर 1
उत्तर प्रदेश
जहां उत्तर प्रदेश
लाइन वहीं से
करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो
प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन
गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में अग्रणी
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश